

सीईईसीसी-आद्री ने अमेरिका के आइसेट-इंटरनेशनल, कोलरैडो के साथ समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किया

प्रकाशनार्थ

पटना, 10 दिसम्बर। नीतिगत अनुसंधान संबंधी थिंक टैंक आद्री स्थित पर्यावरण, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन केंद्र (सीईईसीसी) ने पर्यावरण संसाधन प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में दक्षिण एशिया शोध सहयोग को मजबूती देने के लिए कोलरैडो, अमेरिका के आइसेट-इंटरनेशनल (इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड एनवायरनमेंटल ट्रांजीशन - इंटरनेशनल) के साथ समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किया। अमेरिका के कोलरैडो में अवस्थित समाज विज्ञान की प्रख्यात संस्था आइसेट-इंटरनेशनल दुनिया तथा दक्षिण एशियाई देशों के अनेक हिस्सों में जल प्रबंधन के मुद्दे पर गहराई से काम करती है।

समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर के दौरान अधिक कार्रवाई आधारित अनुसंधान के जरिए जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने पर भी चर्चा हुई।

आद्री के सदस्य सचिव डॉ. शैबाल गुप्ता ने कहा कि सीईईसीसी के जरिए आद्री ने जलवायु परिवर्तन के जिस एजेंडा पर काम शुरू किया उसे अब बिहार राज्य ने भी अच्छी तरह अपना लिया है। बिहार में जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुकूलन के मामले में अन्य राज्यों के सामने मॉडल बनने की संभावना मौजूद है।

सीईईसीसी के निदेशक डॉ. अबिनाश मोहंती ने बताया कि आइसेट के साथ हुआ समझौता कार्रवाई की दिशा में उन्मुखा है और वह इस अनुसंधान का विस्तार बिहार तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र तक करने के प्रति आशान्वित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सीईईसीसी साक्ष्य आधारित अनुसंधानों के जरिए क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से मुक्त रखने के लिए गंभीर प्रयास करने के प्रति कृतसंकल्प है।


बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष प्रो. ए. के. घोष ने मुख्य व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए कहा कि राज्य में 2030 तक जल संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी इसलिए अनुसंधान और साक्ष्य के जरिए बिहार को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से मुक्त रखने के लिए सीईईसीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि पर्षद इस मामले में सीईईसीसी को पूरा सहयोग-समर्थन देगा।

आइसेट-इंटरनेशनल के संस्थापक और वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री केन मैकक्लून ने अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा कि इस समझौता के जरिए होने वाले इस सहयोग से दक्षिण एशिया क्षेत्र और खास तौर पर भारत में अनुसंधान और साक्ष्य निर्माण को और भी ताकत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वी भारत में पर्यावरण संबंधी संसाधनों पर मुख्य रूप से निर्भर रहने वाले लोग जर्बदस्त गर्मी से सबसे अधिक प्रभावित होंगे।

वैज्ञानिक चर्चा सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर प्रभात पी. घोष ने कहा कि समाज विज्ञान और सामाजिक साक्ष्य से जलवायु परिवर्तन को अधिक सह्य बनाया जा सकता है इसलिए यह समझौता एक आरंभिक कदम है।

प्रज्ञा प्रमिता गुप्ता ने राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण कार्य का अवलोकन प्रस्तुत किया और आइसेट-इंटरनेशनल के सीनियर एसोशिएट श्री शशिकांत चोपड़े ने स्पष्ट किया कि अनुसंधान को ताकत देने के लिए जल प्रबंधन, जोखिम एटलस और जल अंकेक्षण सहक्रिया के क्षेत्र होंगे।

विवेक तेजस्वी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। समझौता-पत्र हस्ताक्षर के गोलमेज आयोजन के अवसर पर आद्री की कोषाध्यक्ष डॉ. सुनीता लाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. गोपाल शर्मा, जेडएसआइ और आद्री के अन्य संकाय सदस्यों की भी गरिमामयी उपस्थिति रही।


(अबिनाश मोहंती)